3 रहटगांव में मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार

5 ग्रामीण विकास की राजनीति का सशक्त चेहरा

5 भारतीय राजनीति का अधःपतन

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 08 प्रति सोमवार, 6 जुलाई 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

# मध्य प्रदेश में बीजेपी के चाणक्य हैं कैलाश विजयवर्गीय

## मालवा को बीजेपी का गढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका

जैसे केन्द्रीय बीजेपी में गृहमंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है वैसा ही कैलाश विजयवर्गीय को मप्र बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। सत्ता और संगठन के तमाम मामलों में विजयवर्गीय ने चाणक्य की भूमिका निभाकर पार्टी को मुसीबतों से उबारा है। वह चाहे लोकसभा-राज्यसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो उन्होंने एक संकटमोचक के रूप में सामने आकर बीजेपी को विपरीत स्थितियों से बाहर निकाला है। और कैलाश जी के कारण हर बार बीजेपी एक मजबूत स्थिति में उभरी है। कैलाश

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

विजयवर्गीय के सत्ता-संगठन की कुशलता से राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रभावित है। पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी को फतेह दिलाने के सूत्रधार कैलाशजी हैं। उनकी राष्ट्रीय पहचान विशेष रूप से तब मजबूत हुई जब भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया। उस समय पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन अपेक्षाकृत कमजोर था। विजयवर्गीय ने लगातार दौरे किए, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठित किया तथा बूथ स्तर पर संगठन निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। प्रबंधन की क्षमता और नेतृत्व का विश्वास उन्हें भाजपा की राजनीति में विशिष्ट स्थान दिलाता है। राजनीति में किसी भी नेता की उपयोगिता केवल उसके चुनाव जीतने की क्षमता से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वह संगठन को कितना मजबूत करता है, कार्यकर्ताओं को किस तरह प्रेरित करता है, नेतृत्व के प्रति कितना भरोसेमंद है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी के लिए कितनी प्रभावी भूमिका निभाता है।

### मध्यप्रदेश के लिए अहम हैं विजयवर्गीय

वर्तमान परिस्थितियों में मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार में सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है। बाहर से भले ही सरकार और संगठन में एकता दिख रही हो लेकिन अंदरूनी खानों में देखे तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट, शिवराज सिंह चौहान गुट और प्रहलाद पटेल गुट अंदर ही अंदर सरकार और संगठन को कमजोर करने में लगे हुए हैं। और मोहन सरकार से कहीं काट रहे हैं। खासकर जब से उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जमीनों का मामला उजागर हुआ है।

(शेष पेज 2 पर)

# ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार

## साय सरकार के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि मजदूरों की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। खेतों में अथक परिश्रम करने वाले हजारों भूमिहीन कृषि मजदूर वर्षों से अस्थिर आय, मौसमी रोजगार और आर्थिक असुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। इन्हीं परिवारों को स्थायी आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना आज ग्रामीण कल्याण की एक प्रभावी पहल के रूप में सामने आई है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

### आर्थिक सुरक्षा की नई राह

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है। उनकी आजीविका पूरी तरह कृषि मजदूरी पर निर्भर रहती है। बुवाई, रोपाई और कटाई के मौसम में तो उन्हें रोजगार मिल जाता है, लेकिन खेती के ऑफ सीजन में परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में अनेक परिवार साहूकारों से कर्ज लेने के लिए विवश हो जाते हैं। इसी समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें कठिन समय में आर्थिक सहारा मिल सके। (शेष पेज 2 पर)

### मप्र कांग्रेस में अनुभव, संवाद और संगठनात्मक संतुलन की आवश्यकता

# दतिया उपचुनाव में दिखाना होगा आपसी सामंजस्य

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में समय-समय पर ऐसे अवसर आते हैं, जब किसी दल के सामने केवल चुनावी चुनौती नहीं होती, बल्कि संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने की परीक्षा भी होती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जुड़ी एक रिपोर्ट को लेकर प्रदेश कांग्रेस द्वारा उठाए गए राजनीतिक प्रश्नों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सार्वजनिक रुख ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दिया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या कांग्रेस के भीतर विभिन्न नेताओं के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसके मुद्दे नहीं होते, बल्कि उसके नेताओं के बीच विश्वास, संवाद और संगठनात्मक अनुशासन भी होता है। यदि वरिष्ठ नेताओं के सार्वजनिक वक्तव्य अलग-अलग संदेश देने लगें, तो इसका प्रभाव संगठन की एकजुटता पर भी दिखाई देता है। यही कारण है कि आज प्रदेश कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संगठनात्मक भी है। अभी कांग्रेस के सामने दतिया का चुनाव है।

कमलनाथ के समय कांग्रेस में रहती थी एकजुटता

(शेष पेज 3 पर)

# मालवा को बीजेपी का गढ़ बनाने में कैलाश विजयवर्गीय की है महत्वपूर्ण भूमिका

(पेज 1 का शेष)

तबसे विरोधी गुट हावी होता जा रहा है। और अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाता नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में केवल कैलाश विजयवर्गीय ही एक ऐसे नेता हैं जो विरोधी गुटों को संभाल सकते हैं। लेकिन मोहन सरकार कैलाश जी के मालवा क्षेत्र की उपेक्षा कर उन्हें नाराज करने पर उतारू है। चूंकि मालवा क्षेत्र उनकी कर्मभूमि है और उनकी कर्मभूमि की जो उपेक्षा करेगा उसे कैलाश जी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। विजयवर्गीय के कारण ही आज मालवा बीजेपी का गढ़ बना हैं। यदि सरकार इस गढ़ की उपेक्षा कर रही है तो वह कहीं न कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मालवा को बचाना है तो कैलाश जी को नाराज नहीं किया जा सकता है। मेरा तो मानना है कि केवल मालवा ही नहीं संपूर्ण मध्यप्रदेश में उनका सम्मान है, प्रभाव है।

### विजयवर्गीय की अहमियतः संगठन, रणनीति और नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा

भाजपा में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी भूमिका केवल चुनाव लड़ने या सरकार चलाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे संगठन को मजबूत करने, राजनीतिक रणनीति तैयार करने और कठिन परिस्थितियों में पार्टी के लिए संकटमोचक की भूमिका निभाने के लिए भी जाने जाते हैं। विजयवर्गीय ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं। प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है। वे कई बार विधायक चुने गए और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में नगरीय प्रशासन, उद्योग, आवास तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का यह संयोजन उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं से अलग पहचान देता है। भाजपा नेतृत्व ने हमेशा उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखा है जो सरकार और संगठन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर सकते हैं। भाजपा में उनकी सबसे बड़ी ताकत संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। पार्टी का विस्तार केवल चुनावी भाषणों से नहीं होता, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा करने से होता है। विजयवर्गीय लंबे समय तक इसी कार्य में सक्रिय रहे। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सहज पहुंच और नियमित संवाद ने उन्हें जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया हैं। यही कारण है कि जब भी भाजपा को किसी राज्य में संगठन को नई ऊर्जा देने की आवश्यकता महसूस हुई, नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया।

### बेबाक अंदाज से रखते हैं अपनी बात

कैलाश विजयवर्गीय की एक विशेषता उनकी स्पष्टवादिता भी है। वे कई बार ऐसे बयान देते रहे हैं जो राजनीतिक बहस का विषय बन जाते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि वे बिना लाग-लपेट अपनी बात रखते हैं, जबकि आलोचक इसे विवादास्पद शैली बताते हैं। हालांकि इन विवादों के बावजूद संगठन में उनकी उपयोगिता कम नहीं हुई। इसका प्रमुख कारण यह है कि भाजपा नेतृत्व उनके संगठनात्मक योगदान और चुनावी क्षमता को अधिक महत्व देता है।

कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी पहचान केवल चुनाव जीतने वाले नेता की नहीं, बल्कि संगठन निर्माता, कुशल रणनीतिकार और नेतृत्व के भरोसेमंद सहयोगी की है। उन्होंने नगर राजनीति से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक अपने अनुभव और कार्यशैली के माध्यम से अलग स्थान बनाया है। भाजपा की संगठनात्मक संस्कृति में ऐसे नेताओं का विशेष महत्व होता है जो कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें, चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करें और कठिन परिस्थितियों में पार्टी का मनोबल बनाए रखें। इसी कारण विजयवर्गीय आज भी भाजपा की राजनीति में एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल जनाधार ही नहीं, बल्कि संगठन के प्रति समर्पण, नेतृत्व का विश्वास और लगातार सक्रिय रहने की क्षमता भी किसी नेता की वास्तविक अहमियत तय करती है।

# साय सरकार के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

(पेज 1 का शेष)

### गरीब परिवारों को मिला आत्मविश्वास

यह योजना ग्रामीण समाज के उन परिवारों के लिए आशा की नई किरण बनी है, जिनकी आय पूरी तरह दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहती है। प्रतिवर्ष मिलने वाली सहायता राशि परिवारों को आवश्यक घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का सबसे बड़ा प्रभाव यह देखने को मिला है कि अब अनेक परिवार छोटी-छोटी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए महंगे ब्याज पर कर्ज लेने से बच रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आई है तथा आत्मनिर्भरता का भाव भी विकसित हुआ है।

### पारदर्शी व्यवस्था से बढ़ा विश्वास

योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शी कार्यप्रणाली है। आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है तथा सहायता राशि बिना किसी देरी के पात्र परिवारों तक पहुंच रही है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर और पूरी राशि प्राप्त हो। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है।

### योजना के परिणाम दे रहे सकारात्मक संकेत

योजना के पहले वर्ष 2025 में राज्यभर के 5 लाख 62 हजार 112 पात्र हितग्राहियों को प्रति परिवार 10 हजार रुपये के मान से कुल 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में अंतरित की गई। योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2026 में भी इसका प्रभावी क्रियान्वयन जारी है। इस वर्ष 04 लाख 95 हजार 965 हितग्राहियों को कुल 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस वर्ष योजना के अंतर्गत 22 हजार 28 बैगा-गुनिया परिवारों को भी शामिल किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार विशेष रूप से आदिवासी एवं पारंपरिक समुदायों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

### सत्यापन और ई-केवाईसी पर विशेष ध्यान

भविष्य में किसी भी पात्र परिवार को योजना से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए शासन द्वारा व्यापक स्तर पर भौतिक सत्यापन तथा ई-केवाईसी का कार्य कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा विकासखंड स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कर रहे हैं ताकि वास्तविक भूमिहीन कृषि मजदूरों तक योजना का लाभ समय पर पहुंच सके।

### ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

यह योजना केवल व्यक्तिगत आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। इससे ग्रामीण बाजारों में क्रय शक्ति भी बढ़ रही है। जब परिवारों के हाथ में अतिरिक्त आय आती है तो स्थानीय स्तर पर व्यापार, उपभोग और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलती है। योजना का लाभ विशेष रूप से उन परिवारों को मिल रहा है जो पहले केवल मजदूरी पर निर्भर थे। अब उन्हें न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हो रही है, जिससे वे भविष्य की आवश्यकताओं की बेहतर योजना बना पा रहे हैं।

### समावेशी विकास की दिशा में प्रभावी पहल

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ग्रामीण विकास की उस सोच को मजबूत करती है, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक सहायता के साथ-साथ यह योजना सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान कर रही है। विशेषकर भूमिहीन कृषि मजदूर, अनुसूचित जनजाति समुदाय तथा कमजोर वर्गों के परिवार इस योजना से लाभान्वित होकर अपने जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव का अनुभव कर रहे हैं।

### ग्रामीण समृद्धि का नया अध्याय

आज जब कृषि क्षेत्र में विविधीकरण, आधुनिक तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है, ऐसे समय में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए संचालित यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने यह सिद्ध किया है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, लक्षित और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ किया जाए तो वे लाखों परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती हैं। आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ यह योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास मॉडल की एक महत्वपूर्ण पहचान बनती जा रही है।

# मंडियों में निरंकुश हुआ मंडी प्रशासन, शुरुआती बारिश में खुली व्यवस्थाओं की पोल, किसानों की उपज भीगने को मजबूर

-बद्रीप्रसाद कौरव

**जगत प्रवाह. गाडरवारा।** कृषि उपज मंडियों में वर्षों से चुनाव नहीं होने का खामियाजा अब सीधे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जवाबदेही और नेतृत्व के अभाव में मंडी प्रशासन पर निरंकुशता के आरोप लग रहे हैं। हालात यह हैं कि शुरुआती बारिश ने ही मंडी प्रशासन के रखरखाव और मरम्मत कार्यों की हकीकत उजागर कर दी है। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन किसानों और व्यापारियों से विभिन्न शुल्कों एवं करों के माध्यम से लाखों रुपये की आय तो जुटाता है, लेकिन मंडी शेडों, फर्श, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर कोई गंभीर ध्यान नहीं दिया जाता। बरसात शुरू होते ही कई मंडी शेडों की टीन चादरें टपकने लगी हैं और उनके नीचे रखी किसानों की उपज पानी में भीग रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि हर वर्ष मरम्मत और रखरखाव के नाम पर खर्च दिखाया जाता है तो फिर मंडी शेडों की ऐसी बदहाल स्थिति क्यों है? किसानों का कहना है कि बरसात से पहले टीन शेडों की मरम्मत और निरीक्षण किया जाना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहे। जिले की विभिन्न कृषि उपज मंडियों का यही हाल है।

# क्या कांग्रेस नेताओं में आपसी मतभेद-मनभेद सामने आने लगे?, कमलनाथ के समय कांग्रेस में रहती थी एकजुटता

(पेज 1 का शेष)

इस चुनाव में कांग्रेसियों को आपसी सामंजस्य दिखाने की जरूरत है। नहीं तो दतिया हाथ से निकलने में देर नहीं लगेगी।

## कांग्रेस को एक सूत्र में बांधने का काम किया कमलनाथ ने

ऐसे समय में कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आता है। इसकी वजह केवल उनका लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं, बल्कि विभिन्न विचारों और नेताओं को साथ लेकर चलने की उनकी कार्यशैली भी रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक निर्णयों के साथ-साथ संगठन में संवाद की संस्कृति को भी महत्व दिया। उनके नेतृत्व में कई अवसरों पर अलग-अलग विचार रखने वाले नेताओं ने भी साझा मंच पर काम किया। कमलनाथ का राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि नेतृत्व केवल निर्णय लेने का नाम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार संगठन को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाने की क्षमता भी है। यही कारण है कि उनके कार्यकाल में संगठन के भीतर मतभेद सार्वजनिक विवाद का रूप कम ही लेते दिखाई दिए। वे अक्सर व्यक्तिगत संवाद, नियमित बैठकों और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते रहे।

प्रदेश कांग्रेस के अनेक पुराने कार्यकर्ता मानते हैं कि कमलनाथ की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहज उपलब्धता और संवाद की शैली रही है। चाहे वरिष्ठ नेता हों, युवा कार्यकर्ता हों या जिला स्तर के पदाधिकारी, सभी के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। यही कारण था कि संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक समन्वित दिखाई देती थी।आज जब कांग्रेस आगामी चुनावों की तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रही

है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि संगठन के भीतर सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो। जनता किसी भी दल से यह अपेक्षा करती है कि वह पहले अपने संगठन को मजबूत बनाए, तभी वह प्रदेश के लिए प्रभावी विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।

## कमलनाथ के मिशन और विजन से प्रभावित हैं कांग्रेसी

कमलनाथ के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क उनका प्रशासनिक अनुभव भी है। लगभग चार दशक तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहते हुए उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभाला। उद्योग, निवेश और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में उनके अनुभव का लाभ मध्यप्रदेश को भी मिला। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भले ही लगभग 18 माह का रहा, लेकिन इस दौरान किसानों, उद्योग, निवेश, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई निर्णय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने। यह भी उल्लेखनीय है कि उनके शासनकाल में प्रारंभ की गई कुछ योजनाओं और विकास संबंधी पहलों को बाद की सरकारों ने भी विभिन्न स्वरूपों में आगे बढ़ाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है कि जनहित की योजनाएं सरकार बदलने के बाद भी जारी रहें। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विकास संबंधी पहलें दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर देखी जाती हैं। कांग्रेस के भीतर आज सबसे अधिक आवश्यकता संगठनात्मक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने की है। इसके लिए अनुभवी नेतृत्व और युवा ऊर्जा के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य होगा। कमलनाथ का अनुभव इस दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने हमेशा संगठन को चुनावी मशीनरी के बजाय कार्यकर्ताओं के परिवार के रूप में विकसित करने पर बल दिया। यही कारण है कि आज भी प्रदेश के अनेक जिलों में उनके साथ वर्षों से जुड़े कार्यकर्ताओं का मजबूत आधार दिखाई देता है। राजनीति में समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अनुभव का महत्व कभी कम नहीं होता। चुनाव केवल नारों से नहीं जीते जाते, बल्कि संगठन, रणनीति, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और कार्यकर्ताओं के मनोबल से जीते जाते हैं। इन सभी पहलुओं में कमलनाथ की कार्यशैली को उनके समर्थक उनकी प्रमुख ताकत मानते हैं।

## आपसी मतभेदों से बाहर निकलने की जरूरत

प्रदेश कांग्रेस के सामने आज अवसर भी है और चुनौती भी। यदि संगठन अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवा नेतृत्व की ऊर्जा को एक मंच पर लाने में सफल होता है, तो वह भविष्य में अधिक प्रभावी राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाया जाए और सार्वजनिक स्तर पर एकजुटता का संदेश दिया जाए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी यह समय संगठन की परिस्थितियों का गंभीरता से मूल्यांकन करने का है। अनुभवी नेतृत्व का उपयोग केवल चुनावी रणनीति तक सीमित न रहकर संगठनात्मक मार्गदर्शन में भी किया जा सकता है। कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में लंबा अनुभव अर्जित किया है, संगठन के लिए मार्गदर्शक भूमिका निभा सकते हैं।

मध्यप्रदेश की राजनीति में कांग्रेस यदि भविष्य की मजबूत रणनीति तैयार करना चाहती है, तो उसे अनुभव, संवाद, संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व की संस्कृति को पुनः स्थापित करना होगा। कमलनाथ का राजनीतिक जीवन इन सभी गुणों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।

# रहटगांव में मोटरसाइकिल चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी टिमरनी के निर्देशन में रहटगांव थाना प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज कुमार दुबे की टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। फरियादी केवल राम सोलंकी और अखिलेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने वाहन चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी रामदास काजले ने कबूल किया कि उसने एक महीने पहले रहटगांव के हाट बाजार और नकवाडा ग्राम से बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल चोरी की थी और उसे जाम सिंह उईके को बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की प्लेटिना बाइक जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

# शराब विक्रय करने वाले होटल व ढाबे पर कार्यवाही

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। बस स्टैंड के सामने क्षेत्र में होटल व ढाबा पर निरंतर ग्राहकों को शराब परोसने और बेचने की सूचनाओं पर सिटी कोतवाली टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने पुलिस टीम के साथ छापामार कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस टीम ने बस स्टैंड गेट के पास पूछताछ कार्यालय के पीछे एक बंद कमरे को खुलवाकर वहां से अवैध शराब से भरे दो थैले भी जप्त किए। जहां पर पुलिस ने बैठकर पिलाने की पूरी व्यवस्था भी देखी। वहीं पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस. थोटा के निर्देशन में एसडीओपी जितेंद्र पाठक के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली टीआई गौरव सिंह बुंदेला द्वारा नगर पालिका सीएमओ को पत्र

यात्रा की गाइड और यात्रा की जानकारी लिखकर दोनों होटल के लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा है। वहीं पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 02 जुलाई को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई बस स्टैण्ड के पास होटलों में अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु कोतवाली पुलिस द्वारा बस स्टैण्ड के पास काकाश्री होटल व पहलवान होटल पर दबिश दी गई। जो पहलवान होटल से 18 क्वार्टर ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब एवं काका श्री होटल से 10 क्वार्टर ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब, 40 क्वार्टर देसी प्लेन शराब बरामद हुई। जिस पर पहलवान होटल के मैनेजर आयुष मनवारे पिता द्वारका प्रसाद मनवारे निवासी मेहरागांव इटारसी एवं काका श्री होटल के मैनेजर यश पिता विजय चौकसे निवासी गिन्नी कंपाउंड मीनाक्षी चौक नर्मदापुरम के विरुद्ध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि दोनो होटलों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रथक से की जाएगी।

## सम्पादकीय

# मध्यप्रदेश भाजपा के संगठन में बदलाव के संकेत

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में संभावित बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सत्ता और संगठन, किसी भी राजनीतिक दल के दो ऐसे स्तंभ होते हैं, जिनके बीच बेहतर समन्वय ही चुनावी सफलता और सुशासन का आधार बनता है। ऐसे में यदि संगठन में परिवर्तन की चर्चा हो रही है तो इसे केवल पदों के फेरबदल तक सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि यह आने वाले राजनीतिक समीकरणों और चुनावी रणनीति का भी संकेत है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताता है कि संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा अनुशासित कार्यशैली ने पार्टी को लगातार मजबूत बनाया है। मध्यप्रदेश में भी भाजपा की चुनावी सफलताओं के पीछे मजबूत संगठनात्मक ढांचा प्रमुख कारण रहा है। इसलिए जब भी संगठन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है, उसका उद्देश्य केवल नए चेहरों को जिम्मेदारी देना नहीं होता, बल्कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संगठन को अधिक प्रभावी बनाना भी होता है।

वर्तमान समय में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के मध्य चरण में प्रवेश कर चुकी है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की जिम्मेदारी संगठन पर ही होती है। यदि संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत होगा तो योजनाओं का राजनीतिक लाभ भी अधिक मिलेगा। इसी कारण संगठन में संभावित बदलाव को आगामी चुनावी तैयारी के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। भाजपा की कार्यशैली में समय-समय पर नए नेतृत्व को अवसर देने की परंपरा रही है। पार्टी अनुभव और युवा नेतृत्व के संतुलन पर विश्वास करती है। ऐसे में यदि संगठन में नई जिम्मेदारियां तय होती हैं तो यह आवश्यक होगा कि अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन के साथ युवा कार्यकर्ताओं को भी पर्याप्त अवसर मिले। इससे संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा।

हालांकि संगठनात्मक बदलाव अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आते हैं। लंबे समय से जिम्मेदारी निभा रहे नेताओं की अपेक्षाएं, नए चेहरों की स्वीकार्यता और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखना नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यदि इन पहलुओं का संतुलित समाधान नहीं किया गया तो असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए संगठन में परिवर्तन केवल नामों का बदलाव नहीं, बल्कि संवाद और विश्वास का भी विषय होता है। प्रदेश की राजनीति में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि संगठन में जिम्मेदारी पाने वाले नेताओं का चयन केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर न होकर उनकी कार्यक्षमता, संगठन निर्माण की क्षमता और जनसंपर्क को ध्यान में रखकर किया जाए। भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी उसका कार्यकर्ता है। यदि कार्यकर्ता स्वयं को सम्मानित और सहभागी महसूस करेगा तो संगठन और अधिक मजबूत होगा।

आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव सामने होंगे। ऐसे में संगठन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान, डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग तथा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारियां होंगी। इसलिए आज किया गया संगठनात्मक पुनर्गठन भविष्य की चुनावी रणनीति का आधार भी बन सकता है। भाजपा नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि संगठन में परिवर्तन के साथ निरंतरता भी बनी रहे। पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव और नए नेतृत्व की ऊर्जा का समन्वय ही संगठन की वास्तविक शक्ति बन सकता है। यदि यह संतुलन स्थापित हो जाता है तो संगठन पहले से अधिक प्रभावी होकर उभर सकता है। मध्यप्रदेश भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की संभावनाएं केवल आंतरिक प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि यह भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम भी हो सकती हैं। यदि यह परिवर्तन दूरदर्शिता, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ताओं के सम्मान को केंद्र में रखकर किया जाता है, तो इससे पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। वहीं यदि संवाद और संतुलन की अनदेखी हुई तो संगठनात्मक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। राजनीति में समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक होते हैं, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे कार्यकर्ताओं में विश्वास और जनता के बीच सकारात्मक संदेश कितना स्थापित कर पाते हैं।

# सियासी गहमागहमी

### वीर भारत न्यास में मची कांग्रेस के आरोपों से हलचल

मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित वीर भारत न्यास इन दिनों राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद विभागीय गतिविधियों और न्यास के कार्यों को लेकर नई चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। विपक्ष का दायित्व सरकार और उसके संस्थानों से जुड़े मामलों पर सवाल उठाना है, वहीं सरकार की जिम्मेदारी तथ्यों के आधार पर उन सवालों का जवाब देना और पारदर्शिता बनाए रखना है। यदि कांग्रेस ने किसी अनियमितता, नियुक्ति प्रक्रिया या वित्तीय प्रबंधन को लेकर आरोप लगाए हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग है। दूसरी ओर, केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर किसी संस्था की विश्वसनीयता पर अंतिम निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में तथ्यों, दस्तावेजों और जांच के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वीर भारत न्यास का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र प्रेरणा से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसलिए आवश्यक है कि यह संस्था राजनीतिक विवादों से ऊपर रहकर अपनी साख बनाए रखे। यदि आरोप निराधार हैं तो उनका तथ्यात्मक खंडन होना चाहिए।

### कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पैदल यात्रा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पैदल यात्रा को केवल राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता। भारतीय राजनीति में पदयात्राएं लंबे समय से जनसंवाद और जनसंपर्क का प्रभावी माध्यम रही हैं। जब कोई वरिष्ठ नेता पैदल चलकर लोगों के बीच पहुंचता है, तो उसे जनता की समस्याओं को निकट से समझने और अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। दिग्विजय सिंह अपनी सक्रिय राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न सामाजिक, पर्यावरणीय और जनहित के मुद्दों पर वे लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। उनकी यह यात्रा भी प्रदेश के राजनीतिक माहौल में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस इसे जनता से जुड़ने का अभियान बता रही है, जबकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी इसे आगामी चुनावों की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। किसी भी पदयात्रा की वास्तविक सफलता उसके संदेश और परिणाम से तय होती है। यदि यात्रा के दौरान जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया जाए और उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल हो, तो उसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव दोनों दिखाई देता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिग्विजय सिंह की यह यात्रा कांग्रेस संगठन को कितना नया उत्साह देती है और प्रदेश की राजनीति पर उसका कितना असर पड़ता है।

## हफ्ते का कार्टून

## ट्वीट-ट्वीट

मणिपुर सालों से जल रहा है, और आज फिर नफ़रत और हिंसा की आग में 20 घर राख हो गए।
दो सरकारों और राष्ट्रपति शासन के बावजूद संघर्ष गहराता ही जा रहा है। हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अनगिनत परिवार उजड़ गए हैं - मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुज़र रहा है, उसकी कल्पना भी मुश्किल है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता
@RahulGandhi

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने 20 साल से भ्रष्टाचार पर ही सारा ध्यान लगा दिया है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई को बर्बाद कर दिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 40% अर्थात एक लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। 1895 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। 10 साल में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र कम हो गए हैं।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

## राजवीरों की बात

# जनसेवा, संगठन और ग्रामीण विकास की राजनीति का सशक्त चेहरा पंकजा मुंडे

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे समकालीन भारतीय राजनीति की उन प्रमुख महिला नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, संगठन क्षमता और जनसंपर्क के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका प्रभाव विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में देखा जाता है। वे अपने पिता एवं दिवंगत जननेता गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों को निरंतर मुखरता से उठाती रही हैं। पंकजा मुंडे का जन्म 26 जुलाई 1979 को महाराष्ट्र के बीड जिले में हुआ। उनके पिता गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में गिने जाते थे और केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। उनकी माता का नाम प्रज्ञा मुंडे है। बचपन से ही उन्हें सामाजिक सरोकार, जनसेवा और राजनीतिक संस्कारों का वातावरण मिला, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया।

उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र में प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा के दौरान राजनीति, समाज और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को निकट से समझा। छात्र जीवन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। पिता के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से उन्हें जमीनी राजनीति का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। वर्ष 2014 में गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदलीं। भाजपा नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया और वे महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। उसी वर्ष विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीड जिले की परली विधानसभा सीट से विजय प्राप्त की और पहली बार विधायक बनीं।

महाराष्ट्र सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, जल संरक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने, जल संरक्षण योजनाओं को गति देने तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े अनेक कार्यक्रमों पर कार्य किया। उनके कार्यकाल में ग्रामीण सड़कों, जल संरचनाओं और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। पंकजा मुंडे की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यापक जनसंपर्क है। वे लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करती हैं, किसानों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों से संवाद स्थापित करती हैं। उनके भाषणों में विकास, आत्मनिर्भरता और संगठन की मजबूती प्रमुख विषय रहते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में उनका एक समर्पित जनाधार विकसित हुआ है।

वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक गति दी तथा भाजपा के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। कठिन परिस्थितियों में भी उनका राजनीतिक आत्मविश्वास बना रहा, जिसने उन्हें पुनः संगठन में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने समय-समय पर उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। वे पार्टी के महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उनकी राजनीतिक शैली संघर्ष, संवाद और संगठनात्मक अनुशासन का संतुलित उदाहरण मानी जाती है। सामाजिक क्षेत्र में भी पंकजा मुंडे की सक्रियता उल्लेखनीय है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला स्वावलंबन और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक अभियानों में भाग लेती रही हैं। विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा, महिला उद्यमिता और किसानों के हितों से जुड़े विषयों पर उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उनकी राजनीतिक यात्रा यह दर्शाती है कि लोकतंत्र में विरासत केवल पहचान का माध्यम होती है, जबकि स्थायी स्वीकार्यता निरंतर जनसंपर्क, परिश्रम और संगठनात्मक क्षमता से प्राप्त होती है। उन्होंने अपने पिता की विरासत को केवल आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि स्वयं की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता के आधार पर भी अलग पहचान स्थापित की है। आज पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी के उन प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं, जिनसे भविष्य में महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संगठन के प्रति निष्ठा और विकासोन्मुख दृष्टिकोण उन्हें समकालीन भारतीय राजनीति की प्रमुख महिला नेताओं की श्रेणी में स्थापित करता है।

# मेरे लिए उद्योग केवल निवेश नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है

भारत के विकास की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सपनों की कहानी है जिन्हें समय-समय पर दूरदर्शी नेतृत्व ने दिशा दी। मुझे गर्व है कि मुझे अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में देश की औद्योगिक प्रगति के इस सफर का सहभागी बनने का अवसर मिला। जब मैं केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था, तब मेरा एक ही उद्देश्य था- भारत को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाना। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस आधुनिक भारत का सपना देखा था, वह केवल सूचना प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं था। उनका लक्ष्य भारत को विज्ञान, तकनीक, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल करना था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला।

मैं हमेशा मानता रहा हूं कि उद्योग केवल बड़े-बड़े कारखानों का नाम नहीं है। उद्योग रोजगार पैदा करता है, युवाओं को अवसर देता है, किसानों की आय बढ़ाता है, छोटे व्यापारियों को बाजार उपलब्ध कराता है और किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देता है। यही सोच मेरे प्रत्येक निर्णय के केंद्र में रही। यह सच है कि बिना प्रशिक्षण के रोजगार नही मिलता है। इसलिए मैंने छिंदवाड़ा में कई स्किल सेंटर शुरू किये। जहां हजारों बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में स्किल्ड पाकर देश-विदेश में जॉब कर रहे हैं। जब मैं केंद्र में उद्योग एवं वाणिज्य सहित विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभाल रहा था, तब मैंने कभी यह नहीं सोचा कि विकास केवल दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, सूरत या बेंगलुरु जैसे महानगरों तक सीमित रहना चाहिए। मेरा स्पष्ट विश्वास था कि यदि भारत को वास्तविक अर्थों में विकसित बनाना है तो उद्योगों का विस्तार देश के हर राज्य और हर क्षेत्र तक होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने देश के अनेक राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया। मेरा हमेशा प्रयास रहा कि उद्योग वहां जाएं, जहां रोजगार की सबसे अधिक आवश्यकता है। भारत का प्रत्येक युवा अपने ही प्रदेश और अपने ही जिले में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सके, यही मेरी प्राथमिकता रही।

मध्यप्रदेश से मेरा विशेष भावनात्मक रिश्ता रहा है। मैंने हमेशा महसूस किया कि प्राकृतिक संसाधनों, कृषि क्षमता और भौगोलिक स्थिति के बावजूद यह प्रदेश अपनी औद्योगिक संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा था। इसलिए जब भी अवसर मिला, मैंने मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक वातावरण विकसित करने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए हरसंभव प्रयास किए। मेरा विश्वास था कि किसी भी राज्य का विकास केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होता। जब तक निजी निवेश, उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक व्यापक आर्थिक परिवर्तन नहीं आ सकता। इसी सोच के साथ उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर लगातार कार्य किया गया।

मैंने हमेशा निवेशकों से कहा कि मध्यप्रदेश केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संभावनाओं की भूमि है। यहां पर्याप्त भूमि है, प्राकृतिक संसाधन हैं, मेहनतकश युवा हैं और देश के मध्य में स्थित होने के कारण उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति भी उपलब्ध है। यदि इन सभी विशेषताओं का सही उपयोग किया जाए

**कमलनाथ**
(मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता)

तो मध्यप्रदेश देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है। मेरे लिए उद्योग लगाने का अर्थ केवल फैक्ट्री स्थापित करना नहीं था। मैं चाहता था कि उद्योगों के साथ सड़कें बनें, बिजली पहुंचे, कौशल विकास हो, छोटे व्यवसाय विकसित हों और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। किसी भी उद्योग की वास्तविक सफलता तभी होती है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

विकास किसी एक व्यक्ति या एक सरकार की संपत्ति नहीं होता। यदि कोई अच्छी योजना आगे बढ़ती है और जनता को उसका लाभ मिलता है तो इससे बड़ी संतुष्टि किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं हो सकती। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि सरकारों को विकास के प्रश्न पर राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। यदि किसी पूर्व सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसे रोकना नहीं, बल्कि आगे बढ़ाना चाहिए। यही लोकतंत्र की परिपक्वता और सुशासन की पहचान है।

औद्योगिक विकास के साथ-साथ मैंने लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को भी समान महत्व दिया। मेरा मानना रहा है कि भारत की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हमारे छोटे उद्यमी हैं। यदि उन्हें पूंजी, तकनीक और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो वे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आज पूरी दुनिया तकनीक और नवाचार के युग में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे समय में भारत के लिए यह आवश्यक है कि हम आधुनिक उद्योगों, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, निर्यात और अनुसंधान को प्राथमिकता दें। यह केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का भी प्रश्न है।

मैंने हमेशा युवाओं को भारत की सबसे बड़ी पूंजी माना है। यदि उन्हें अवसर, प्रशिक्षण और संसाधन मिलें तो वे दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। इसलिए मेरी सोच हमेशा रोजगार सृजन केंद्रित रही। उद्योगों का विस्तार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।मुझे इस बात का भी संतोष है कि आज देश में औद्योगिकीकरण, विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को लेकर जो व्यापक वातावरण बना है, उसमें अतीत में किए गए अनेक प्रयासों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक पीढ़ी उसमें अपना योगदान देती है।

मेरे सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र हमेशा यही रहा है कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए स्थायी परिवर्तन लाना होना चाहिए। यदि मेरे प्रयासों से देश के किसी युवा को रोजगार मिला, किसी परिवार की आय बढ़ी, किसी जिले में उद्योग स्थापित हुआ या किसी राज्य के विकास को नई गति मिली, तो मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। हमें केवल उन संभावनाओं को सही दिशा देने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि यदि उद्योग, कृषि, तकनीक और कौशल विकास एक साथ आगे बढ़ें तो भारत विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्तियों में स्थायी स्थान प्राप्त करेगा।

यही मेरा विश्वास था, यही मेरा प्रयास रहा और यही मेरा संकल्प आज भी है कि विकास का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उद्योगों की रोशनी महानगरों से निकलकर गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचे और भारत आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय का भी उदाहरण बने। यही सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण का मार्ग है।

# भारतीय राजनीति का अधःपतन

रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता,
विचारक और
समाजवादी नेता

भारतीय राजनीति निरंतर पतन से अधःपतन की ओर बढ़ रही है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद सत्ताधारी कांग्रेस का नेतृत्व लगभग नियंत्रण मुक्त हो गया था। जो लोकप्रियता खोने के भय या सम्मान के चलते महात्मा गांधी की सलाह कुछ सुनी या मानी जाती थी उसकी भी संभावना समाप्त हो गई थी। 1952 के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिये कई प्रकार के अनैतिक उपक्रम शुरू किये। केरल की विरोधी सरकार को दलबदल कर गिराया और ऐसे कई प्रयोग कालान्तर में 1957 और 1962 के बाद कई सूबों में किये गये। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जिनके नाम से मंडल कमीशन जाना जाता है, वे बिहार के मधेपुरा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक चुनकर आये थे और राज्य सरकार में मंत्री थे। उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच दिया, सरकार गिराई गई और कुछ समय के लिये वे मंत्री बने और फिर उन्हें भी हटा दिया गया। बाद में वही विंदेश्वरी मंडल 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय संगठन कांग्रेस याने मुरारजी कांग्रेस के साथ चले गये। उनके इन्हीं रिश्तों के चलते जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार से उपप्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मंत्रीमंडल से हटाया गया, तब उनके जनाधार को कम करने के लिये जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिये आयोग बनाने की बात स्वीकार की और जब वह आयोग बना तब उसका अध्यक्ष उन्हीं वी.पी. मंडल को बनाया, जो पिछड़े वर्ग को धोखा देकर कांग्रेस के हाथ के खिलौना बने थे।

देश में दलबदल की शुरुआत कराने वाली भी कांग्रेस और उसके मुखिया थे। जहां कहीं भी प्रतिपक्ष का आधार बढ़ा उसे कमजोर करने के लिये कांग्रेस नेतृत्व ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाये। दल के भीतर रहकर, दल के निर्णय के खिलाफ कार्य करने की परिपाटी भी कांग्रेस ने ही शुरू की थी। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक कारण यह भी था कि कांग्रेस संगठन व सरकार के बीच गहरे मतभेद व टकराव थे। स्व. जवाहर लाल नेहरू ने यह परिपाटी शुरू कर दी थी कि संगठन की तुलना में सत्ता सर्वोपरि है और उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में धीरे-धीरे सत्ता का केंद्रीयकरण किया इसके परिणामस्वरूप या तो संगठन को अप्रभावी बनाया या अपने कब्जे में ले लिया। स्व. जवाहर लाल नेहरू के जीवनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बनी थीं तथा वह सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने लगी थी। राजनैतिक निर्णयों को करने के लिये स्वतः प्रधानमंत्री पार्टी के नेताओं को इंदिरा जी के पास जाने के इशारे देने लगे थे। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष, अलिखित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी प्रक्रिया को 1971 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया तथा अप्रत्यक्ष व अलिखित तौर पर सत्ता का नियंत्रक अपने बेटे संजय गांधी को बनाया था। 1969 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिये स्वः नीलम संजीव रेड्डी को प्रत्याशी बनाया, इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी उपस्थित थीं। उन्होंने न किसी नाम का प्रस्ताव किया और न कोई राय दी व चुप बैठी रहीं तथा बाद में वीवी गिरि को निर्दलीय तौर पर खड़ा कराया, उनका समर्थन किया, कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी को ऐनकेन प्रकारेण जिताया। कांग्रेस में अनुशासनहीनता की विधिवत और उच्च स्तरीय शुरुआत तो स्वतः श्रीमती गांधी ने की थी। इसी प्रकार की अनेकों घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, उन्होंने पार्टी को व्यक्ति केन्द्रित या स्वः केन्द्रित बनाया। कांग्रेस के संगठन व ढांचे का विभाजन और पिछलग्गूपन यहीं से शुरू हुआ तथा महात्मा गांधी के जीवनकाल में जो परंपरा रही थी, कि सत्ता की तुलना में संगठन सर्वोपरि है, उस आदर्श परंपरा को मिटा दिया गया। इस व्यक्तिपरक और सत्तापरक सत्ता के प्रभुत्व के सिद्धांत की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी और अब धीरे-धीरे यह परिपाटी लगभग सभी पार्टियों में पहुंच चुकी है।

पार्टियों में अब अनुशासनहीनता वक्ती अपराध है याने चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा अब सबकी स्थिति विशेषतः संगठन की स्थिति दोयम दर्जे की है। जो लोग चुनाव का टिकिट नहीं मिलने पर, मंत्री नहीं बनने पर या मुख्यमंत्री नहीं बनने या हटाये जाने पर या केंद्रीय मंत्री नहीं बनाये जाने या हटाये जाने पर किसी सिद्धांत के लिये नहीं बल्कि स्वार्थों के लिये पार्टी छोड़ते हैं, दलबदल करते हैं और बाद में बहुमत में कमी रहती है तब उन्हें ही दलों की सत्ता व संगठन पर वापिसी के नाम पर ससम्मान बुलाती और सत्ता में हिस्सेदारी देती है, जो कार्यकर्ता और विशेषतौर पर जमीनी कार्यकर्ता दल के नीति सिद्धांत से बंधे रहते हैं, उन दल बदलुओं को उनके ही सिर पर थोप दिया जाता है। याने कुल मिलाकर सिद्धांत यह हो गया है कि कोई भी दल हो उसे सत्ता चाहिए, सत्ता के लिये जो भी अनैतिक कार्य करना हो वह करने को सत्ताधारी पक्ष तैयार रहता है। आजकल यह जुमला चल गया है कि भाजपा वाशिंग मशीन है और यह इसलिये कि जिन लोगों को भाजपा ने विपक्ष के रूप में भ्रष्टाचारी कहा, सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराये। 100-200 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ के आरोप लगाये परंतु अपनी सत्ता बनाने के लिये उन्हें ही ससम्मान वापिस लाकर पूरी पार्टी के सिर पर बैठा दिया गया। स्व. अजीत पंवार को सरकार बनाने के लिये एनसीपी से तोड़कर उपमुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, उनको निर्दोष सिद्ध करने के लिये सीबीआई केस वापिस ले लिये गये और जब वे वापस एनसीपी में चले गये तो उसी सीबीआई ने बेशर्मी के साथ पुनः कार्यवाही की शुरुआत की। क्या सीबीआई के यह कार्य केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर नहीं थे? 2023 के विधानसभा चुनाव के समय फिर उन्हें मिलाया, फिर केस हटाया, फिर उपमुख्यमंत्री बनाया। याने जिन राजनैतिक अपराधों या राजैनतिक अनैतिकता की शुरुआत कांग्रेस ने अपने व्यापक राष्ट्र सत्ता के दौरान की थी उन्हीं तरीकों को और अधिक बेशर्मी के साथ भाजपा आगे ले जा रही है। हरियाणा में दलबदल का खेल छुटपुट चलता रहा परंतु स्व. देवीलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिये भजनलाल को जो कांग्रेस के थे, पूरे विधायकों के साथ जनता पार्टी में शामिल कराकर मुख्यमंत्री बनाया गया। 1980 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और देवीलाल को लगभग बहुमत होने के बाद भी रोकने के लिये कि वह मुख्यमंत्री न बन सकें, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी के मुख्यमंत्री व मंत्रियों याने सारे मंत्रीमंडल को वापिस कांग्रेस में शामिल करा दिया। क्या बिगड़ जाता अगर कांग्रेस एक दो राज्यों में अपने विरोधी दलों की सरकार को बर्दाश्त करती और अपनी पार्टी को नैतिक तरीकों से मजबूत बनाती।

नैतिकता के सिद्धांत को तो कांग्रेस ने पहले आम चुनाव के बाद ही त्याग दिया दिया था जब समाजवादियों ने कांग्रेस से निकलकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस के चिन्ह पर निर्वाचित विधायकों ने विधायक पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिये तथा मध्यावधि चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े तथा अपनी ही पार्टी के पुराने साथियों को हराने के लिये कांग्रेस ने अनैतिक रास्ते अपनाये। यह सर्वविदित तथ्य है कि आचार्य नरेन्द्र देव को हराने के लिये कांग्रेस ने बाबा राघवदास को खड़ा किया और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिये वोट मांगे। अगर आचार्य वह चुनाव जीत जाते, कांग्रेस पार्टी नैतिक मूल्यों का सम्मान करती और उन्हें हटाने के लिये हिंदुत्व कार्ड नहीं खेलती तो देश में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती तथा कटटरपंथ की राजनीति का उदय नहीं होता। आज कांग्रेस के ही अनैतिक व घिनौने अस्त्रों का इस्तेमाल, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। दुखद यह है कि 1950 से लेकर 1960 के दशक तक राजनीति व चुनाव में, पैसे का चलन उतना नहीं हुआ था। समाज में भी कमोवेश नैतिक मूल्यों का सम्मान होता था। चुनाव में पैसे का खुलकर उपयोग 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। उमा वासुदेव ने जिन्होंने उनकी आत्मकथा लिखी थी उसमें श्रीमती इंद्रा गांधी को एक प्रश्न के उत्तर में यह कहते हुये उद्धत किया है कि श्मैं चुनाव इतने महंगे कर दूंगी कि कोई विरोधी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। जिस राजनैतिक गंदगी की शुरुआत राजनीति में पैसे के चलन को कांग्रेस ने शुरू किया था अब उसी का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर भाजपा कर रही है। भाजपा को उद्योगपतियों ने इस वर्ष 6600 करोड़ रुपये का चंदा दिया और कांग्रेस को 1900 करोड़ का। याने अब भाजपा की सत्ता उद्योगपतियों को अधिक पसंद है बजाय कांग्रेस के। अब तो हालात इतने चिंताजनक है कि पंचायतों के चुनावों में लाखों से लेकर करोड़ों रुपया खर्च होने लगे। मतदाता पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव में अपवाद छोड़कर सीधे रुपया लेकर वोट दे रहे हैं। जो लोग सीधे रुपया नहीं ले रहे हैं वे सरकार से कुछ हजार रुपये की सुविधाओं के बदले में वोट दे रहे हैं। यह भी लगभग उसी प्रकार वोट को बेचना है जिस प्रकार नगद रुपया देकर वोट को बेचना है। दिल्ली का उच्च मध्यमवर्ग और मध्यवर्ग जिसकी मासिक आमदनी औसतन लाख दो लाख प्रतिमाह से अधिक है, वह भी 200 यूनिट बिजली, 300 लीटर मुफ्त पानी, के लिये वोट देता है। अगर सामान्य व गरीब मतदाता 5-10 हजार रुपयों को लेकर अपना वोट बेचता है तो हमारा पढ़ा लिखा संभ्रांत मतदाता साल के 30-40 हजार रुपया और 5 साल के लिये लाख डेढ़ लाख रुपये में अपना वोट बेचता है। यह राजनीति के पतन का भयानक दौर है। पहले मुस्लिम मतदाता ने केवल कांग्रेस को वोट दिया, अपने मतों का धुरवीकरण किया और अब उसके प्रति उत्तर में हिंदु मतदाताओं का धुव्रीकरण शुरु हुआ तथा हिंदु मतदाता भी अब आमतौर पर भाजपा का समर्थक मतदाता बन रहा है। पहले कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराकर उनके वोट लेती थी, अब बहुसंख्यक हिंदु संप्रदाय को भाजपा डरा कर उनका भयादोहन कर रही है। दल बदल अब इतना फैल चुका है कि जो राजनीति व राजनैतिक दलों के लिये कैंसर जैसा हो गया है। अब जो पार्टी सरकार से हटती है उसके लोग बड़े पैमाने पर पार्टी को छोड़कर सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं जो कि एक चलन बन गया है। मैं उन सभी लोगों से जो सिद्धांत पर चलना चाहते हैं, अपील करता हूँ कि इस अनैतिकता की गिरावट, भयंकर आंधी और तूफान में भी आप तिनके के समान खड़े रहें। आंधी, तूफान जायेगा परंतु ये तिनके ही कल राजनीति की नैतिकता के मार्गदर्शक और आधार बनेंगे।

## छत्तीसगढ़ के किसानों को खरीफ फसल के लिए नहीं उर्वरकों की कमी

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों को खरीफ की फसलों के लिए उर्वरकों की कमी नहीं होगी। सरकार ने पिछले साल की भांति इस वर्ष की उतने ही उर्वरक देने की योजना बनाई है। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने यूरिया वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के बराबर खरीफ 2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्व लागू 80 प्रतिशत वितरण सीमा समाप्त कर दी गई है, जिससे किसानों को खेती के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने दुलदुला स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण कर खाद-बीज की उपलब्धता, कृषि ऋण वितरण एवं किसानों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसानों को नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी समय समिति में यूरिया का स्टॉक कम होने के कारण पूरी पात्रता के अनुसार उर्वरक नहीं मिल पाता है, तो स्टॉक उपलब्ध होते ही शेष मात्रा भी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों को उर्वरक की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सहकारी समिति में उपलब्ध खाद-बीज के भंडारण, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित कृषि ऋण तथा किसानों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद, बीज एवं कृषि ऋण समय पर उपलब्ध कराया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। कलेक्टर व्यास ने समिति में पहुंचे किसानों से सीधे संवाद कर खेती की तैयारियों, उर्वरकों की उपलब्धता एवं कृषि संबंधी समस्याओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि इन उर्वरकों के उपयोग से फसलों को संतुलित पोषण मिलता है, लागत में कमी आती है और भूमि की उर्वरता भी संरक्षित रहती है।

# यूरोप में गर्मी का आतंक, हमें सावधान रहने की जरूरत

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हालिया रिपोर्टों के अनुसार यूरोप में भीषण गर्मी से हजारों अतिरिक्त मौतें हुई हैं। दक्षिण यूरोप में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है। 2025 के एक अध्ययन के अनुसार 12 यूरोपीय शहरों में 10 दिनों की हीटवेव के दौरान लगभग 2,300 अतिरिक्त मौतें हुईं, और 2025 में Nature Medicine में प्रकाशित एक बड़ी रिसर्च के मुताबिक पूरे यूरोप में 2024 में लगभग 62,700 गर्मी-संबंधी मौतें दर्ज की गईं। इटली और ब्रिटेन में भी गर्मी है। फ्रांस और इटली में लोग गर्मी देखकर हैरान हैं। ऐसा लगता है कि गर्मी लंबी होने वाली है क्योंकि तापमान शुरुआत में बढ़ चुका है। 50 वर्ष पहले जून में ऐसी हीट वेव असामान्य बात थी। मगर अक्सर देखने को मिल रहा है। पिछले 25 वर्षों में स्पेन में हीट वेव नौ बार देखे जा चुके हैं। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो यूरोप का नाम सुनते ही मेरे जहन में एक तस्वीर उभरती थी- हरियाली से लिपटा कोई शांत देश, जहाँ हल्की धूप, ठंडी हवाएँ और शांति का आभास होता था। वो तस्वीर अब टूट रही है। यूरोप अब गर्म हो रहा है। नहीं, सिर्फ मौसम नहीं बदला बल्कि वक्त की करवट है ये। और इस करवट के नीचे दबी हुई है हमारी लापरवाही, हमारी लालच, और हमारी चुप्पी। अब तो यूरोप का आसमान भी तपने लगा है, और वहाँ की जमीनें प्यास से चटकने लगी हैं। 2024 की गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े, और 2025 उसे पीछे छोड़ने को तैयार है। विशेषज्ञों ने दुनिया को चेताया है कि अगली बार हीटवेव कहीं अधिक जानलेवा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन यों ही बढ़ता रहा तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। यूरोप के कई देशों में इस वर्ष गर्मी ने भारी कहर मचाया है। तापमान में असहनीय वृद्धि और लगातार आने वाली लहरें अनेक देशों में सामान्य जीवन को कठिन कर रही हैं। शहरों में कड़ाके की गर्मी ने बिजली और पानी की मांग बढ़ा दी है, जिससे आउटर सप्लाई बाधित हुई और बिजली कटौती जैसी समस्याएँ सामने आईं। बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर यह प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता गर्मी से तुरंत नहीं निपट पाती। कई राज्यों में अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित रोगियों की संख्या बढ़ गई और जानलेवा हालतों की खबरें भी आने लगीं।

पर सवाल उठता है कि क्या हमें वाकई फर्क पड़ रहा है? ये सिर्फ यूरोप का मामला नहीं है। बहुतों को लगता है कि यूरोप दूर है। वहाँ गर्मी है तो क्या हुआ? हमारे यहाँ तो हर साल लू चलती है। लेकिन इस सोच में ही सबसे बड़ा धोखा छिपा है। यूरोप का जलना, हिमालय की बर्फ को पिघलने का न्यौता है। ग्लेशियर का पिघलना उसी का प्रभाव है। वहाँ की नदियाँ सूखेंगी तो व्यापार और भोजन की कड़ियाँ टूटेंगी। वहाँ की आग अगर बेकाबू हुई तो उसकी राख यहाँ तक पहुँचेगी। कभी यूरोप क्लाइमेट चेंज पर भाषण देता था, अब वो खुद प्रयोगशाला बन गया है। हर जंगल की आग, हर सूखती नदी और हर गर्मी से मरता नागरिक अब ये चिल्लाकर कह रहा है- "हमने देर कर दी है। अब तुम मत करना।"

मुझे एक बात साफ़ लगती है कि ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये व्यवस्था के चरमराने की कहानी है। यूरोप में बिजली की माँग बढ़ी, तो कोयले से चलने वाले प्लांट फिर से चालू हो गए। पानी की किल्लत हुई, तो भूमिगत स्रोत खींचे जाने लगे। मतलब ये कि आग बुझाने के नाम पर हम उसी ईंधन से खेल रहे हैं जिसने ये आग लगाई है। क्या ये विडंबना नहीं है कि जलवायु परिवर्तन से बचने की कोशिशें भी उसी सोच से निकल रही हैं जिसने ये संकट पैदा किया? यूरोपियन यूनियन की ग्रीन डील एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज है, लेकिन ज़मीन पर इसके असर बहुत धीमे हैं। नेट जीरो के लक्ष्य जब तक सिर्फ तारीखों में दर्ज होंगे, तब तक तापमान न कैलेंडर देखेगा, न घोषणाएं। पर्यावरण सम्मेलनों में शब्द बहुत होते हैं, पर इच्छाशक्ति बहुत कम। जब तक जलवायु को लेकर कोई निर्णय लेने से पहले आर्थिक लाभ-हानि का हिसाब लगाया जाएगा, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ सरकारों की नहीं। पूरे समाज की है।

सवाल ये नहीं है कि यूरोप गर्म क्यों हो रहा है। सवाल ये है कि क्या हम ठंडे पड़ चुके हैं? हमारी संवेदना ठंडी हो चुकी है। जब ग्रीस में आग लगती है, जब फ्रांस में बुजुर्ग गर्मी से मरते हैं, जब इटली की नदियाँ सूखती हैं तब हमारे देश की बहसें पेट्रोल के दाम, क्रिकेट की हार-जीत या टीवी शो पर होती हैं। यूरोप की बढ़ती गर्मी एक प्राकृतिक घटना नहीं है। ये एक सामूहिक असफलता है। और अगर हम अभी नहीं जागे, तो आगे सिर्फ तापमान नहीं बढ़ेगा बल्कि उम्मीदें भी बुझ जाएँगी।

# किताबी ज्ञान में अव्वल, वास्तविक जिंदगी से अनजान

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। भारत में आज शिक्षा पहले से कहीं अधिक सुलभ है। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ है और युवाओं के हाथों में डिग्रियों का अंबार लग रहा है। लेकिन इस चमक-दमक के बीच एक बुनियादी प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, क्या हम वास्तव में शिक्षित हो रहे हैं, या केवल परीक्षा पास करने की कला सीख रहे हैं? आज की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी दौड़ में बदलती जा रही है जहाँ गति तो है, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है। हम बच्चों को कठिन सिद्धांत, लंबे पाठ्यक्रम और हर हाल में अव्वल आने का जुनून तो सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर पा रहे। स्कूल और कॉलेज से निकलकर जब युवा कार्यस्थल, व्यवसाय या सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, तो उसे अक्सर महसूस होता है कि किताबों में सीखी गई बातों और वास्तविक जीवन की अपेक्षाओं के बीच एक बड़ी खाई मौजूद है। हमारे विद्यार्थी जटिल गणितीय समीकरण और ऐतिहासिक घटनाएँ याद कर लेते हैं, लेकिन संवाद कौशल, टीमवर्क, समय प्रबंधन, आर्थिक समझ, नेतृत्व और समस्या-समाधान जैसे जीवनोपयोगी कौशलों में पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि डिग्री हाथ में होने के बावजूद अनेक युवा व्यावहारिक चुनौतियों के सामने असहज दिखाई देते हैं।

## आंकड़ों के आईने से

यह चिंता केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आंकड़ों से भी प्रमाणित होती है। ASER 2024 के अनुसार विद्यालयों में नामांकन दर लगभग 98 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है, लेकिन सीखने की गुणवत्ता अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी कक्षा से नीचे स्तर की पुस्तकें पढ़ने और बुनियादी गणितीय प्रश्न हल करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

इसी प्रकार India Skills Report और विभिन्न रोजगार सर्वेक्षण बताते हैं कि स्नातक होने वाले युवाओं का बड़ा वर्ग उद्योगों और आधुनिक कार्यस्थलों की अपेक्षाओं के अनुरूप पूरी तरह तैयार नहीं है। समस्या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में उतारने की क्षमता की कमी है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) भी संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता और व्यावहारिक निर्णय लेने की दक्षता को लेकर चुनौतियों की ओर संकेत करता है। दुनिया भी अब शिक्षा की नई परिभाषा लिख रही है। UNESCO की रिपोर्टें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि भविष्य की शिक्षा केवल सूचना आधारित नहीं हो सकती। रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग, सांस्कृतिक समझ और व्यावहारिक कौशल ही आने वाले समय की सबसे बड़ी आवश्यकताएँ होंगी।

यदि हम अपने इतिहास की ओर देखें तो भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली इस दृष्टि से कहीं अधिक संतुलित दिखाई देती है। तक्षशिला और नालंदा केवल शिक्षा संस्थान नहीं थे, बल्कि जीवन निर्माण के केंद्र थे। वहाँ ज्ञान के साथ कौशल, अध्ययन के साथ व्यवहार और शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया जाता था। विद्यार्थी केवल जानकारी लेकर नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि लेकर निकलते थे। इसके विपरीत, वर्तमान व्यवस्था बच्चों में प्रतिस्पर्धा तो पैदा कर रही है, लेकिन धैर्य और असफलता को स्वीकार करने की क्षमता विकसित नहीं कर पा रही। अंक और रैंक की दौड़ में बच्चे जीतना तो सीख रहे हैं, लेकिन हार से सीखना नहीं। परिणामस्वरूप छोटी-सी असफलता भी कई बार उनके आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर देती है।

विडंबना यह है कि हम बच्चों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो पढ़ाते हैं, लेकिन एक पौधा लगाकर उसे धैर्यपूर्वक विकसित करना नहीं सिखाते। हम आर्थिक सिद्धांत पढ़ाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत बजट बनाना नहीं सिखाते। हम नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन सक्रिय नागरिक बनकर समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अभ्यास नहीं कराते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस समस्या को पहचाना है और कौशल विकास, अनुभवात्मक शिक्षा तथा समग्र मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया है। यह एक सकारात्मक पहल है, लेकिन इसकी सफलता तभी संभव होगी जब स्कूल, परिवार और समाज मिलकर शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें घर के छोटे-छोटे कार्यों, वित्तीय समझ, सामाजिक उत्तरदायित्व, स्वयंसेवा, कला, खेल और स्थानीय समस्याओं के समाधान से जोड़ना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि जीवन को समझना और समाज में सार्थक योगदान देना होना चाहिए। शायद अब समय आ गया है कि हम बच्चों से यह पूछना थोड़ा कम करें कि "आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया?" और यह पूछना शुरू करें कि "आज तुमने जीवन और समाज से क्या नया सीखा?"

क्योंकि अंततः सफल वही नहीं होता जिसने सबसे अधिक किताबें रटी हों, बल्कि वह होता है जिसने सीखी हुई बातों को जीवन में उतारना सीख लिया हो। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जानकारी से भरा हुआ मस्तिष्क नहीं, बल्कि संवेदनशील, आत्मविश्वासी, संतुलित और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। यदि हम आज इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर सकें तो आने वाली पीढ़ियों को केवल डिग्रियाँ ही नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की सही दिशा भी मिल सकेगी।

## 07 हजार करोड़ की राशि से और मजबूत होगा उत्तराखण्ड का सड़क नेटवर्क

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग किया। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित सड़क एवं अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक एवं रणनीतिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन तथा आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सुदृढ़ एवं आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय का अनुरोध किया। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु राज्य सरकार को लगभग रूपये 750 करोड़ लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की गई। इसके साथ ही NHO के अंतर्गत 05 प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग रूपये 2966 करोड़ है। इनमें श्रीनगर बाईपास का PMC, पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार मार्ग की चार-लेनिंग, लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास की alignment, मझोला से खटीमा के आबादी भाग में चार-लेन विस्तार तथा रामनगर–रानीखेत (मोहन) मार्ग का सुदृढ़ीकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की रूपये 530.11 करोड़ की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र अवमुक्त किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने आगामी अर्धकुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)